भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3126

06 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

पंजाब में पीएमएवाई-यू के अंतर्गत शहरी आवास परियोजनाएं

†3126. डॉ. राज कुमार चब्बेवालः

क्या आवासन और शहरी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने पंजाब में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) और प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 (पीएमएवाई-यू 2.0) के अंतर्गत शहरी आवास परियोजनाओं की स्थिति की समीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत स्वीकृत, निर्माणाधीन और पूर्ण किए गए आवासों का शहर और जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत पंजाब से किसी प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है और यदि हां, तो लाभार्थियों की संख्या कितनी है और स्वीकृत वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(घ) 31 मार्च, 2025 को स्मार्ट सिटी मिशन (एससीएम) के समापन के पश्चात् पंजाब के स्मार्ट शहरों अर्थात् अमृतसर, जालंधर और लुधियाना में परियोजनाओं की स्थिति का ब्यौरा क्या है तथा पूर्ण, जारी और लंबित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और यदि कोई विलंब हुआ है, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) एससीएम के पश्चात् पंजाब में शहरी अवसंरचना, किफायती आवास और जलवायु-अनुकूल शहरी विकास के लिए निरंतर वित्तीय और तकनीकी सहायता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (ग): आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) दिनांक 25.06.2015 से देश-भर के पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं सहित सभी मौसमों के अनुकूल पक्के आवास उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) का कार्यान्वयन कर रहा है।

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के कार्यान्वयन से प्राप्त अनुभवों से मिली सीख के आधार पर आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने योजना में बदलाव किया है और देश-भर के शहरी क्षेत्रों में 1 करोड़ अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से दिनांक 01.09.2024 से "सबके लिए आवास" मिशन के अंतर्गत पीएमएवाई-यू 2.0 का शुभारंभ किया है। पीएमएवाई-यू 2.0 का कार्यान्वयन चार घटकों अर्थात् लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराया आवास (एआरएच) तथा ब्याज सहायता योजना (आईएसएस) के माध्यम से किया जा रहा है। योजना के दिशा-निर्देश https://pmay-urban.gov.in/uploads/guidelines/Operational-Guidelines-of-PMAY-U-2.pdf लिंक पर उपलब्ध हैं।

पंजाब राज्य द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्ताव के आधार पर मंत्रालय ने पीएमएवाई-यू के अंतर्गत अब तक कुल 1.21 लाख आवासों को स्वीकृति प्रदान की है। इनमें से दिनांक 13.07.2026 की स्थिति के अनुसार 1.14 लाख आवासों का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है तथा 1.03 लाख आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है/लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त, दिनांक 13.07.2026 की स्थिति के अनुसार मंत्रालय ने पंजाब में पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत कुल 37,778 आवासों को स्वीकृति प्रदान की है। इनमें से 16,897 आवासों का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है तथा 2,700 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है/लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं।

पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत पंजाब राज्य के लिए कुल 537.06 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता का अनुमोदन किया गया है, जिसमें से राज्य द्वारा प्रस्तुत अनुपालनों के आधार पर

254.66 करोड़ रुपये राज्य को जारी किए जा चुके हैं। गत तीन वर्षों के दौरान पंजाब में पीएमएवाई-यू तथा पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत स्वीकृत, निर्माणाधीन तथा पूर्ण किए गए आवासों का शहर-वार एवं जिला-वार विवरण https://pmay-urban.gov.in/PHQ/LSUQ-3126.pdf पर उपलब्ध है।

मंत्रालय, पंजाब सहित देश-भर में पीएमएवाई-यू तथा पीएमएवाई-यू 2.0 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस, क्षेत्रीय दौरों तथा अन्य निगरानी तंत्रों के माध्यम से पंजाब सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ इन योजनाओं की प्रगति की नियमित समीक्षा करता है।

(घ) एवं (ङ): पंजाब राज्य में स्मार्ट सिटीज मिशन (एससीएम) के अंतर्गत तीन शहरों अर्थात् अमृतसर, जालंधर तथा लुधियाना का चयन किया गया था। राज्य द्वारा दिनांक 31.03.2026 की स्थिति के अनुसार उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, कुल 4,485 करोड़ रुपये लागत की 204 परियोजनाओं में से 4,148 करोड़ रुपये लागत की 190 परियोजनाएं पूर्ण की जा चुकी हैं। दिनांक 31.03.2025 को स्मार्ट सिटीज मिशन (एससीएम) के समापन के साथ ही मिशन के अंतर्गत कोई बजटीय प्रावधान शेष नहीं है। तथापि, सरकार विभिन्न चल रही प्रमुख योजनाओं तथा संस्थागत पहलों के माध्यम से पंजाब राज्य में शहरी इन्फ्रास्ट्रक्चर, किफायती आवास तथा जलवायु-अनुकूल शहरी विकास को निरंतर सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

स्मार्ट सिटीज मिशन (एससीएम) के पूर्ण होने के पश्चात प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 (पीएमएवाई-यू 2.0), अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) 2.0, स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (एसबीएम-शहरी) 2.0 तथा अन्य शहरी विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत, निर्धारित योजना दिशा-निर्देशों तथा राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान की जा रही है।

****